चीनी टेलीविजन कार्यक्रमों द्वारा भ्रामक प्रचार

1382. **श्री सत्यपाल मलिक :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान हिमाचल प्रदेश के सूचना मंत्री ने चीनी टेलीविजन कार्यक्रमों द्वारा भ्रामक प्रचार से सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों पर पड़ रहे बुरे प्रभाव तथा हमारे दूरदर्शन कार्यक्रमों के उन क्षेत्रों तक न पहुंचने के बारे में कोई शिकायत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रसारण मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि (संसदीय सचिव) ने 25-5-1988 को हुए राज्यों के सूचना मंत्रियों के सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया था कि क्योंकि हिमाचल प्रदेश पर्वतीय तथा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहां आदिवासियों की पर्याप्त जनसंख्या है तथा इसकी लम्बी सीमा चीन के साथ लगती है अत: केन्द्रीय सरकार को इस राज्य को विशेष प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए । तथापि, राज्य के किसी भी भाग चीनी टी०वी० सिग्नल के संग्रहण के बारे में उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया ।

(ख) दूरदर्शन की सातवीं योजना में हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थापित की जाने वाली निम्नलिखित परियोजनाएं शामिल हैं :—

(1) शिमला में 1 कि.वा. उच्च शक्ति ट्रांसमीटर सहित टी.वी. स्टूडियो केन्द्र ।

(2) मंडी, बिलासपुर तथा धर्मशाला में अल्प शक्ति (100 वाट) के टी. वी. ट्रांसमीटर ।

(3) चम्बा, हमीरपुर, कल्पा, केलांग एवं ऊना में अति अल्प शक्ति (2 × 10 वाट) के ट्रांसमीटर ।

(4) सोलन में ट्रांसमीटर ।

मंडी, बिलासपुर एवं चम्बा में टी. वी. ट्रांसमीटर पहले ही स्थापित तथा चालू हो गए हैं । चालू वित्तीय वर्ष (1988-89) के दौरान धर्मशाला, कल्पा, केलांग तथा ऊना के ट्रांसमीटरों के स्थापित तथा चालू हो जाने की उम्मीद है । जहां तक हमीरपुर में लगाए जाने वाले ट्रांसमीटर का प्रश्न है, इसे हिमाचल प्रदेश सरकार के परामर्श से राज्य के किसी अन्य स्थान पर लगाने के बारे में विचार किया जा रहा है क्योंकि हमीरपुर पहले ही कसौली स्थित उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर से टी.वी. सेवा प्राप्त कर रहा है । सोलन में ट्रांसमीटर के 1989 के अन्त तक लगाए जाने की उम्मीद है । जहां तक शिमला में टी. वी. स्टूडियो केन्द्र और उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर को स्थापित करने का संबंध है, यह एक लम्बी अवधि की परियोजना है जिसके चालू होने के लिए 1990-91 के दौरान तैयार हो जाने की उम्मीद है। दूरदर्शन की उपरिउल्लिखित परियोजनाओं के कार्यान्वित होने पर हिमाचल प्रदेश राज्य में टी. वी. सेवा में पर्याप्त सुधार हो जाएगा । सेवा में और विस्तार, दूरदर्शन विस्तार की भावी योजनाओं में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

Basic Amenities in Slums

1383. SHR D. B. CHANDRE GOWDA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have any plan to make slums as livable as possible and also to help the slum dwellers to upgrade by constructing houses;

(b) if so, the details in this regard;

(c) whether Government propose to direct the State Government to take effective steps to upgrade slums; and

(d) if so, what other measures Government propose to take to improve the standard of slum dwellers in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (d) The present policy of the Government emphasises an environmental improvement of urban slums in situ rather than their massive clearance and re-location. The State sector scheme of Environmental Improvement of Urban Slums is in operation in this regard. Under the Scheme, basic amenities like drinkign water supply, community baths and latrines, street lighting, paving of existing lanes and pathways etc. are provided in urban slums. Funds are provided in the State Annual Plans and the State Governments formulate and implement appropriate projects under the Scheme in accordance with their needs and priorities.

The World Bank assisted urban development projects in operation in Bombay, Calcutta, Madras and other cities have also substantial slum upgradation component. Considering the acute conditions in Bombay, the Government has also decided to provide special non-plan grant of Rs. 100 crores to the Government of Maharashtra during 7th Plan for tackling the acute problems of housing and slums in Bombay.

अनुसूचित जनजातियों को छूट

1384. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के रोजगार कार्यालयों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को कोई छूट प्रदान नहीं की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार भविष्य में इस श्रेणी के व्यक्तियों को कोई छूट प्रदान करने का विचार रखती है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री बिंदेश्वरी दुबे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गौतमपुरी, दिल्ली में सड़कों का चौड़ा किया जाना

1385. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गौतमपुरी में सड़कों को चौडा किये जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा किये जाने की संभावना है, और किन-किन विशिष्ट स्थानों पर उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित सड़कों को चौडा किये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर हां हो, तो उन पर कुल कितनी धनराशि खर्च किये जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि गौतमपुरी में सड़कों को चौड़ा करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) तथा (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

विधवाओं को रोजगार

1386. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विधवाओं को रोजगार कार्यालयों में अपने नामों के पंजीयन की एक वर्ष की अवधि के समाप्त होने के बाद भी नौकरियां नहीं दी जाती